



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29112024-259018  
CG-MH-E-29112024-259018

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 945]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2024/ अग्रहायण 6, 1946

No. 945]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024/ AGRAHAYANA 6, 1946

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुंबई, 27 नवम्बर, 2024

सं. के.का.:मासवि.:औसवि.:2024-25:295— बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श से और भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारियों के) सेवा विनियम, 1979 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियमों को बनाया है, अर्थात्:-

- (i) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।  
(ii) इन विनियमों में अन्यथा प्रावधानित किए गए मामलों को छोड़कर, ये विनियम 01 नवंबर, 2017 से प्रभावी माना जाएगा।
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसे आगे इन विनियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) में विनियम 3 में, -  
(i) खंड (एफ) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(एफ) “चिकित्सा सुविधाओं और अवकाश किराया रियायत के उद्देश्य से “परिवार” का तात्पर्य अधिकारी के पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित अविवाहित संताने (जिसमें सौतेले और विधिवत दत्तक लिए गए बच्चे शामिल हैं) चालीस प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पूर्णतः आश्रित शारीरिक और मानसिक रूप से

दिव्यांग भाई या बहन, विधवा पुत्रियां और आश्रित तलाकशुदा या अलग हुई पुत्रियां, अविवाहित, तलाकशुदा, पति द्वारा परित्यक्त या अलग हुई बहनें, विधवा बहनें और माता-पिता जो अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित हैं। ∴

स्पष्टीकरण -

- (i). "पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य" का अर्थ परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक नहीं है। यदि माता-पिता में से किसी एक की आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल आय ₹12,000/- प्रति माह से अधिक है, तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूरी तरह से आश्रित नहीं माना जाएगा।
- (ii). एक विवाहित महिला अधिकारी परिवार की परिभाषा के अंतर्गत अपने प्राकृतिक माता-पिता या सास-ससुर को शामिल कर सकती है, लेकिन दोनों को नहीं, बशर्ते कि माता-पिता या सास-ससुर उस पर पूरी तरह आश्रित हों।

**नोट (1):** चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना में, सभी अधिकारियों (अर्थात् पुरुष या महिला) द्वारा आश्रित माता-पिता या सास-ससुर में से किन्हीं दो को शामिल किया जाएगा। अधिकारी के पास आश्रितों में से किसी एक या दोनों को बदलने का विकल्प होगा।

**नोट (2):** किसी अधिकारी के शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को उनकी आय मानदंड के अधीन, आयु या वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, आश्रित माना जाएगा;"

- (ii) उक्त विनियमनों के विनियम 3 में, खंड (i) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-  
"प्रबंध निदेशक" का तात्पर्य बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है।

### 3. उक्त विनियमनों के विनियम 4 में,-

- (i) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (7) एवं (8) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-  
"(7) 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी, प्रत्येक ग्रेड के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :-  
(ए) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹ 116120 – 3220/4 – 129000

वेतनमान VI = ₹ 104240 - 2970 /4 - 116120

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

वेतनमान IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

(सी) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹ 63840 -1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

वेतनमान II = ₹ 48170–1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹ 36000 -1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

**स्पष्टीकरण** - 31 अक्टूबर, 2017 को प्रभावी वेतनमानों द्वारा शासित होने वाले प्रत्येक अधिकारी, 1 नवंबर, 2017 से इस उप-विनियम में उल्लिखित वेतनमान में चरण-दर-चरण आधार पर फिट किया जाएगा, अर्थात् संबंधित वेतनमानों में प्रथम चरण से प्रारंभ करके समतुल्य चरणों में और वार्षिक वेतन वृद्धि सामान्य रूप से वार्षिक तिथि पर ही होगी, बशर्ते अन्यथा प्रावधान न किया गया हो।

- (8) उप-विनियम (1), (2), (3), (4), (5), (6) और (7) में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारियों की सेवा अनिवार्य रूप से रखने की आवश्यकता है।
- (9) (ए) 1 नवम्बर, 2012 से प्रभावी, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा :-  
वेतनमान I – III - मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता  
वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 10 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता  
वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 11 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता
- (9) (बी) 1 नवम्बर, 2017 से प्रभावी, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:-  
वेतनमान I – III - मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता.  
वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 19 प्रतिशत और उस पर लागू महंगाई भत्ता.  
वेतनमान VI - VII - मूल वेतन का 20 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता.

**नोट:** उप-विनियमन 9 के खंड (ए) और (बी) में उल्लेखित विशेष भत्ते तथा उस पर लागू महंगाई भत्ते को नई पेंशन योजना, भविष्य निधि और ग्रेज्युटी सहित पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा .

#### 4. उक्त विनियमनों के विनियम 5 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“(1) विनियम 4 के उप-विनियम (7) और (8) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2017 से वेतन वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्: -

- (ए) विनियम 4 के उप-विनियम (7) और (8) में उल्लिखित वेतनमानों में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन, वार्षिक आधार पर अर्जित होगी और जिस माह में वे देय होंगी, उस माह के प्रथम दिन दी जाएंगी;
- (बी) अपने-अपने वेतनमान में अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को आगे की वेतन वृद्धि, जिसमें स्टेगनेशन वेतन वृद्धि भी शामिल है, केवल निम्नलिखित खंड (सी) एवं (डी) में निर्दिष्ट अनुसार, अगले उच्चतर स्केल में प्रदान की जाएगी, बशर्ते वे दक्षता बाधा (efficiency bar) को पार कर लें।”
- (सी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I के अधिकारी, जो उच्चतर वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद खंड (b) के अनुसार मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II का वेतनमान पा रहे हैं, वे सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के अंतराल पर स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जो अधिकतम पाँच होंगी, जिनमें से पहली दो वेतनवृद्धियां 1990/- रुपये प्रत्येक और अगली तीन वेतन वृद्धियां 2220/- रुपये प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी चौथी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र हो ;

- (डी) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी, जो खंड (बी) के अनुसार उच्चतर वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III का वेतनमान पा रहे हैं, वे सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के अंतराल पर ₹2220/- प्रत्येक की पांच स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी चौथी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र हो ;

- (ई) मूल रूप से मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के अधिकारी अर्थात् वे अधिकारी जो मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में भर्ती हुए हैं या पदोन्नत होकर इस वेतनमान में आए हैं, वे छह स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से उच्चतम वेतनमान तक पहुँचने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर पहली चार वेतनवृद्धियाँ ₹2220/- प्रत्येक, दी जाएंगी, और अगली दो स्टेगनेशन वेतन वृद्धियाँ ₹2500/- प्रत्येक, चौथी स्टेगनेशन वेतन वृद्धि प्राप्त करने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की पूर्ण सेवा पर दी जाएंगी।

बशर्ते कि छठी वेतनवृद्धि पांचवीं वेतनवृद्धि के जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2017, जो भी बाद में हो, जारी की जाएगी ;

- (एफ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV में अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुँचने के बाद, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए दो स्टेगनेशन वेतन वृद्धि हेतु पात्र होंगे, जिनमें से पहली स्टेगनेशन वेतन वृद्धि 2500/- रुपये की होगी और दूसरी स्टेगनेशन वेतन वृद्धि 2730/- रुपये की होगी:

बशर्ते कि अधिकारी प्रथम स्टेगनेशन वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, द्वितीय स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा ;

- (जी) वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 2017 तक बैंक में अपनी सेवा के दौरान स्केल I से स्केल IV तक ठहराव वेतन वृद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें पहले निर्धारित तीन वर्षों की अवधि को दो वर्षों की अवधि में पुनः समायोजित किया जाएगा, अर्थात् उनके उच्चतम वेतनमान तक पहुँचने की तिथि से। अधिकारी को 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी रूप से संशोधित अवधि के अनुसार स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए काल्पनिक रूप से पात्र माना जाएगा, जो सेवानिवृत्ति लाभों के योग्य होगा। हालांकि, इस संशोधित और पुनः समायोजित स्टेगनेशन वेतन वृद्धि अवधि के कारण वित्तीय लाभ 1 नवंबर, 2020 से या वास्तविक अधिकार तिथि से, जो भी बाद में हो, प्रदान किया जाएगा;

- (एच) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2020 से, जो भी बाद में हो, रु. 2970/- रुपये की एक स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि ऐसी वेतनवृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है।

**स्पष्टीकरण** - इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतन वृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा तथा अधिकारियों के विशेषाधिकार, सुविधाएं, कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके मूल पद के अनुसार जारी रहेंगे."

- (ii) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (जी) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(एच) 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी, अन्य सभी परिस्थितियाँ समान होने पर, व्यवसायिक योग्यता वेतन की मात्रा नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधित होगी:-

#### सारणी

जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट I परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद 1020 रुपये प्रति माह.
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग पास कर लिए हों	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद 1020 रुपये प्रति माह. (ii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के दो वर्ष बाद 2550 रुपये प्रति माह:

बशर्ते कि जो अधिकारी भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) की योग्यताएँ प्राप्त करने के बाद वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचते हैं, उन्हें ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किश्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किश्तें पहली किश्त देने की तारीख के संदर्भ में होगी."

(iii) (ए) उप-विनियम (3) में, तालिका के पश्चात खंड (एफ) के अंतर्गत नोट को हटाया जाए :-

(बी) उप-विनियम (3) में, तालिका के पश्चात खंड (एफ) के अंतर्गत निम्नानुसार खंड शामिल किया जाएगा अर्थात:

"(जी) 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी, अन्य सभी परिस्थितियाँ समान होने पर, निर्धारित व्यक्तिगत वेतन और मकान भत्ते की राशि निम्नलिखित दरों पर होगी और यह सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगी:-

#### सारणी

क्रम सं.	वेतन वृद्धि घटक ( रु.)	1 नवंबर, 2017 को वेतन वृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता ( रु.)	जब बैंक का आवास प्रदान किया जाता है, तो कुल निर्धारित व्यक्तिगत वेतन ( रु.)
	(1)	(2)	(3)
1	1990	53	2043
2	2220	59	2279
3	2500	66	2566
4	2730	73	2803
5	2970	79	3049
6	3220	86	3306

#### नोट:

- इस उप-विनियमन के खंड (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) एवं (जी) में सारणी के कॉलम (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक आवास उपलब्ध कराया गया है।
- मकान किराया भत्ते के लिए पात्र योग्य अधिकारियों के लिए निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन उस तालिका के कॉलम (1) और (2) में निर्धारित कुल राशि होगी, और हाउस रेंट भत्ते की राशि जो संबंधित अधिकारी द्वारा उस समय प्राप्त की जाती है जब संबंधित वेतनमान के अंतिम वेतन वृद्धि के बाद उसे अर्जित किया गया हो, जैसा कि विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6) और (7) में विनियोजित है;
- केवल वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 या उससे पहले बैंक की सेवा में हैं, वे ही अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष बाद निश्चित व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र होंगे, जिस वेतनमान में उन्हें रखा गया है।
- 1 नवंबर, 1999 से, निश्चित व्यक्तिगत वेतन के जारी होने के कारण पेशेवर योग्यताभत्ते के जारी होने की समय-सारणी में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा कि उप-विनियम (2) के स्पष्टीकरण (c) में है:

बशर्ते कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किश्त, जो पूर्ववर्ती उपबंधों के कारण एक वर्ष के लिए आगे खिसक गई है और 1 नवम्बर, 1999 को या उसके पश्चात जारी होने वाली है, वह अधिकारी को इसी दिनांक से जारी की जाएगी और यदि कोई दूसरी किश्त हो, तो वह 1 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी।

- निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतनवृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभ के लिए सम्मिलित किया जाएगा।

- (vi) अधिकारी जिन्होंने उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, वे वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) एवं (जी) में उल्लिखित निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन प्राप्त करेंगे।
5. उक्त विनियमन के विनियम 20 के उप-विनियम (1) के खंड (सी) में, “प्रबंध निदेशक” शब्दों के स्थान पर “प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे. से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. उक्त विनियमनों के विनियम 21 में,-
- (i) उप-विनियम (6) के पश्चात्, स्पष्टीकरण (ए) और (बी) को हटा दिया जाएगा;
- (ii) उप-विनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
- “(7) 1 नवंबर, 2017 से, महंगाई भत्ता 6352 अंकों पर आधारित समग्र भारतीय औसत श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में हर 4 अंकों के वृद्धि या गिरावट पर 0.07% वेतन के हिसाब से देय होगा.”
- स्पष्टीकरण - इस उप-विनियमन के प्रयोजनों के लिए,-
- (ए) महंगाई भत्ते के प्रयोजन के लिए “वेतन” का तात्पर्य मूल वेतन से है जिसमें स्टेगेशन वेतनवृद्धि तथा विशेष भत्ता शामिल है;
- (बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी) व (एच) में निर्दिष्ट में निर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन महंगाई भत्ते के लिए गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
7. “इन विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “(1) 1 नवम्बर, 2017 से,-
- (ए) जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय आवास प्रदान किया गया हो, तो उस अधिकारी से उस वेतनमान के पहले चरण के मूल वेतन का 0.50 प्रतिशत या आवास का मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;
- (बी) जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई हो, तो वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता पाने के लिए पात्र होगा, अर्थात्:-

#### सारणी

क्रम सं.	कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
1.	(2)	(3)
2.	प्रमुख “ए” श्रेणी के शहर और गुप ए में परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9.0%
3.	क्षेत्र I अन्य स्थान, गुप बी परियोजना क्षेत्र के और गोवा राज्य के केंद्र	वेतन का 8.0%
4.	अन्य स्थान	वेतन का 7.0%

बशर्ते, यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, उसके द्वारा आवास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.50 प्रतिशत का आधिक्य होगा, लेकिन अधिकतम मकान किराया भत्ते की सीमा तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित उपर्युक्त दरों के 150 प्रतिशत तक होगी।

नोट :- अधिकारियों द्वारा उनके स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावों को भी पूर्ववत् 150 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

8. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,-

(ए) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) व (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) 1 नवंबर, 2017 से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित किसी स्थान पर कार्यरत है, तो उसे उस स्थान के लिए कॉलम (3) में उल्लिखित दर पर नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देय होगा।

सारणी

क्रम सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र I और उससे ऊपर के केंद्र तथा गोवा राज्य	रु . 1400/- प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्य की राजधानियाँ तथा चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	रु . 1150/- प्रति माह

(2) 1 नवम्बर, 2017 से विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी.

(3) 1 नवंबर, 2017 से, यदि कोई अधिकारी समूह 'ए' या समूह 'बी' के अंतर्गत आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में सेवा कर रहा है, तो वह क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार, समूह 'ए' के लिए 600/- रुपये प्रति माह या समूह 'बी' के लिए 525/- रुपये प्रति माह की दर पर परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता पाने का पात्र होगा।

(4) 1 नवम्बर, 2020 से, यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण किसी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और उसके एक या अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह सभी बच्चों के संबंध में, बाद वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक 1650/- रुपये प्रति माह के मध्य-शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा भत्ता बंद तब समाप्त हो जाएगा, जब सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना बंद कर देंगे.

(5) 1 नवंबर, 2020 से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है, या वह अपने वेतन के अलावा, प्रतिनियुक्ति भत्ता वेतन का 7.75 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 6000/- रुपये प्रति माह और उस स्थान पर बैंक की सेवा में होने पर मिलने वाले अन्य भत्तों को प्राप्त कर सकता है:

बशर्ते कि जहां उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले नियुक्त था, तो उसे अपने वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो अधिकतम 3000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है:

इसके अलावा, यदि अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह वेतन का 4 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का पात्र होगा, जो अधिकतम 3000 रुपये प्रति माह के अधीन होगा.

(बी) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(8) 1 नवंबर, 2017 से, यदि कार्य दिवस के दौरान कार्य के घंटे न्यूनतम दो घंटे के अंतराल के साथ विभाजित होते हैं, तो अधिकारी 300 रुपये प्रति माह की दर से स्प्लीट ड्यूटी भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे।”

(सी) उप-विनियम (10) के लिए, नोट (ए) और (बी) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(10) 1 नवंबर, 2017 से, अधिकारी हिल एंड फ्यूल भत्ता निम्न तालिका के अनुसार प्राप्त करने के पात्र होंगे, अर्थात्: सारणी

क्र.सं.	स्थान	मूल्य
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर या उससे अधिक लेकिन 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले स्थान और मडिकेरी नगर (मेरकारा)	वेतन का 2% अधिकतम रु 1125/- प्रति माह के अधीन
2.	1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु .1500/- प्रति माह के अधीन
3.	3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु 3000/- प्रति माह के अधीन

(डी) उप-विनियम (10) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

“(11) 1 नवंबर, 2017 से, एक अधिकारी 600/- रुपये प्रति माह के शिक्षण भत्ते और उस पर महंगाई भत्ते के लिए पात्र होगा.”

(12) 1 नवंबर 2017 से, उन अधिकारियों को, जो सिटी कम्पेन्सेटरी भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में पदस्थ हैं, ₹700/- प्रति माह का एक निश्चित भत्ता दिया जाएगा। यह निश्चित भत्ता महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभों जैसे पेंशन (राष्ट्रीय पेंशन योजना सहित), भविष्य निधि और ग्रेज्युटी की गणना के लिए मान्य नहीं होगा।

(13) वित्तीय वर्ष 2020-21 से, कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन सभी अधिकारियों को वार्षिक रूप से बैंक के परिचालन लाभ या शुद्ध लाभ के आधार पर सामान्य वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा। कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन का मैट्रिक्स, जो बैंक के वार्षिक कार्यनिष्पादन पर आधारित होगा, निम्नलिखित रूप में वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के दिनों की संख्या में देय राशि का निर्धारण करेगा:

क्रम.सं.	परिचालन लाभ में प्रति वर्ष वृद्धि दर	दिनों की संख्या, जिसके लिए वेतन (मूल+ महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा.
(1)	(2)	(3)
1.	<5%	शून्य
2.	5% से 10%	5 दिन
3.	>10% से 15%	10 दिन*
4.	>15%	15 दिन*

\*3 रा और 4 था स्लैब केवल तभी देय हैं जब बैंक को शुद्ध लाभ हो. यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत और उससे अधिक है, लेकिन शुद्ध लाभ नहीं है, तो दूसरे स्लैब के न्यूनतम 5 दिनों का भुगतान किया जाएगा .”

9 उक्त विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“1 नवंबर, 2017 से, कोई भी अधिकारी स्वयं तथा परिवार के लिए चिकित्सकीय व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि अधिकारी द्वारा स्वप्रमाणित आधार पर निम्न तालिका अनुसार दावा की गई राशि के लिए लेखा विवरण के साथ समर्थित व्यय किए जाने का प्रमाणपत्र दिया जाए।



## सारणी

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रुपये 10300/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यकारी श्रेणी	रुपये 12300/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो

**नोट: -** (i) एक अधिकारी को अप्राप्त चिकित्सा सहायता को संचित करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते यह कभी भी ऊपर दिए गए अधिकतम राशि से तीन गुना अधिक न हो;

(ii) वर्ष 2017 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति को दो महीने, यानी नवंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा."

**10. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -**

"(2) उप-विनियम (1) में किसी भी प्रावधान के बावजूद, बैंक को यह अधिकार होगा कि वह 1 नवंबर, 2017 से एक अधिकारी को आवासीय सुविधा प्रदान करे, जिसके लिए अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा, वह राशि जो उसके मूल वेतन के पहले चरण के 0.50 प्रतिशत के बराबर होगी, या उस आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो:

बशर्ते कि यदि अधिकारी को उस आवास में फर्नीचर प्रदान किया जाता है, तो बैंक द्वारा अधिकारी से अपने पदस्थापित वेतनमान के पहले चरण के 0.10 प्रतिशत के बराबर एक अतिरिक्त राशि वसूली जाएगी:

बशर्ते कि जहां ऐसी आवासीय सुविधा बैंक द्वारा प्रदान की जाती है, वहां बिजली, पानी, गैस और रखरखाव के शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे."

**11. उक्त विनियम के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) में, प्रावधान के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -**

"स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(ए) वर्ष 2017 या उसके बाद के किसी भी वर्ष में प्रयुक्त नहीं किए गए आकस्मिक अवकाश अगले पांच वर्षों में समाप्त हो जाएंगे.

(बी) 1 नवंबर, 2020 से, अधिकारी द्वारा प्राप्त न किए गए आकस्मिक अवकाश को चिकित्सा आधार पर अनुमति दी जाएगी और ऐसे प्राप्त न किए गए आकस्मिक अवकाश के लिए किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते यह अवकाश चार दिनों से अधिक का न हो।"

**12. उक्त विनियम के विनियम 33 में:-**

(ए) उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) 1 जून, 2015 से, विशेषाधिकार अवकाश दो सौ सत्तर दिनों से अधिक नहीं जमा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां अवकाश हेतु आवेदन किया गया हो, और इसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि, विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस दिनों तक सीमित होगा :

बशर्ते कि वर्ष 2020 से, अधिकारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में अपनी पसंद के किसी भी त्योहार पर पांच दिनों के हिसाब से विशेष अवकाश नकदीकरण का पात्र होगा और जिन अधिकारियों ने 1 जनवरी, 2020 तक पचपन वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सात दिनों के हिसाब से विशेष अवकाश नकदीकरण के पात्र होंगे.

(बी) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(5) विशेषाधिकार अवकाश लेने की इच्छा रखने वाले अधिकारी को सामान्यतः अवकाश किराया रियायत के प्रायोजन को छोड़कर ऐसा अवकाश लेने के अपने इरादे की कम से कम दस दिन पूर्व सूचना देना होगी।

(6) अधिकारी के चिकित्सकीय अवकाश खाते में कोई अवकाश न होने की स्थिति में, चिकित्सा के आधार पर लिए गए विशेषाधिकार अवकाश को विशेषाधिकार अवकाश के उपयोग की गणना में नहीं माना जाएगा।"

13. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(5) महिला अधिकारी आठ वर्ष या उससे कम उम्र के अपने बच्चों की चिकित्सा के लिए चिकित्सकीय अवकाश ले सकती हैं।" बशर्ते चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।"

14. उक्त विनियमों के विनियम 35 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"35. अतिरिक्त चिकित्सकीय अवकाश- (1) 1 जनवरी, 1989 से, जहां किसी अधिकारी ने चौबीस वर्ष की सेवा की है, तो वह प्रत्येक अतिरिक्त सेवा वर्ष के लिए एक महीने का अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जो कि अधिकतम तीन महीने तक हो सकता है।

(2) 1 नवम्बर, 2017 से, यदि किसी अधिकारी ने तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो वह प्रत्येक अतिरिक्त सेवा वर्ष के लिए एक महीने का अतिरिक्त बीमार अवकाश प्राप्त करने के योग्य होगा, जो अधिकतम तीन महीने तक हो सकता है

बशर्ते कि अधिकारी की पूरी सेवा के दौरान चिकित्सकीय अवकाश की कुल संख्या सात सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि यदि 29 जून, 1999 या उसके बाद अतिरिक्त बीमार अवकाश लिया गया है, तो अतिरिक्त अवकाश का कम्प्यूटेशन नियमन 34 के उप-नियमन (2) के अनुसार अनुमत की जाएगी।"

"16. उक्त विनियमन के विनियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"36 मातृत्व अवकाश. -

(1) कोई महिला कर्मचारी अपनी सेवा की अवधि के दौरान किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह के लिए और अपनी पूरी सेवा अवधि में बारह माह की अवधि के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी: बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि आठ माह की होगी;

इसके अलावा, मातृत्व अवकाश को आकस्मिक अवकाश छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ साथ जोड़ा जा सकता है।

(2) गर्भपात, चिकित्सीय गर्भावस्था या गर्भसमापन के मामले में, महिला कर्मचारी सक्षम चिकित्सक, यानी एक योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ के चिकित्सा प्रमाण पत्र या परामर्श के आधार पर अधिकतम छह सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश ले सकती है। विशेष या असाधारण परिस्थितियों में, यदि गर्भपात, चिकित्सीय गर्भपात या गर्भसमापन से संबंधित जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, तो सक्षम चिकित्सक (योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ) की सलाह पर यह अवधि छह सप्ताह से अधिक भी हो सकती है, लेकिन किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह तक और पूरी सेवा अवधि में बारह माह तक ही लिया जा सकता है;

(3) बारह माह की कुल अवधि के भीतर, महिला कर्मचारी हिस्टरेक्टमी (गर्भाशय निष्कासन) के मामले में अधिकतम साठ दिनों का अवकाश भी ले सकती है।

**नोट :** यदि किसी कर्मचारी ने बारह माह का मातृत्व अवकाश ले लिया है और उसे समाप्त कर दिया है, तो चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त पंद्रह दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा;

(4) एक निःसंतान महिला कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में एक बार एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए अधिकतम नौ माह का अवकाश ले सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :अर्थात्:-

(i) अवकाश केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए दिया जाएगा;

- (ii) बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए और कर्मचारी को ऐसे अवकाश की स्वीकृति के लिए गोदनामा (एडॉप्शन डीड) प्रस्तुत करना होगा ;
- (iii) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी भी बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश पाने के पात्र हैं;
- (iv) यह अवकाश उन जैविक माताओं को भी मिलेगा जिनके बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो;
- (v) यह अवकाश पूरी सेवा अवधि के दौरान बारह माह की कुल पात्रता के भीतर ही लिया जा सकेगा।"
- (5) बारह माह की कुल अवधि के भीतर, स्त्री रोग संबंधी बीमारियों के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भी अधिकतम तीस दिनों के लिए अवकाश का लाभ लिया जा सकता है, अर्थात्:-
- एयूबी (असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव);
  - ओवेरियन ट्यूमर;
  - ट्यूबेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी रिवर्सल;
  - प्रसवोत्तर अवसाद (पीपीडी);
  - प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच);
  - तीव्र पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोग (तीव्र पीआईडी);
  - डिसफंक्शन गर्भाशय रक्तस्राव; डिसफंक्शन (डीयूबी).
- (6) पितृत्व अवकाश के मामले में, 1 जून, 2015 से अधिकतम दो बच्चों के अभिभावक पुरुष कर्मचारी अपनी पत्नी के प्रसव के दौरान पंद्रह दिन के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे और यह अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है:
- वशर्ते कि अवकाश बच्चे के जन्म की तारीख से पंद्रह दिन पहले या छह महीने तक ली जा सकेगी:
- आगे यह भी प्रावधान है कि उपर्युक्तानुसार पितृत्व अवकाश दो जीवित बच्चों वाले पुरुष कर्मचारी को एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए दिया जाएगा."
17. उक्त विनियमन के विनियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "37. असाधारण अवकाश,-
- (1) कोई अधिकारी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम चौबीस माह के लिए वेतन की हानि सहित असाधारण अवकाश के लिए पात्र होगा.
- (2) कोई अधिकारी किसी एक अवसर पर तीन मास से अनधिक अवधि के लिए असाधारण अवकाश ले सकेगा तथा अत्यधिक चिकित्सीय परिस्थितियों में वह किसी एक अवसर पर चार मास तक का असाधारण अवकाश ले सकेगा.
- नोट:** चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश लेने के कारण कर्मचारी की वरिष्ठता में कोई हानि नहीं होगी.
18. उक्त विनियमन के विनियमन 37ए के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "37ए विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश,-
- (1) 1 नवम्बर, 2020 से कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसे अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा, जब वह शाखा जहां अधिकारी कार्यरत है या वह स्थान जहां वह निवास कर रहा है, कफ्यू, दंगे, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि से प्रभावित हो.
- (2) 1 नवम्बर, 2020 से शारीरिक या आर्थोपेडिकली दिव्यांग अधिकारी चार दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे.
- (3) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश तथा कोई विशेष अवकाश भी प्रदान किया जा सकेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए."

19. उक्त विनियमनों के विनियमन 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ए) विराम भत्ता- 1 नवंबर, 2020 से, तालिका के कॉलम (1) में दिए गए श्रेणी या वेतनमान में कोई अधिकारी कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी दरों पर 'प्रतिदिन' विराम भत्ते का हकदार होगा, अर्थात्:-

**तालिका**

क्रम सं.	अधिकारी की श्रेणी /वेतनमान	मेट्रो रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र I रु.	अन्य स्थान रु.
	(1)	(2)			
2	वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	2700	1950	1650	1425
3	वेतनमान IV और V के अधिकारी	2250	1950	1650	1425
4	वेतनमान I और III के अधिकारी	1950	1650	1425	1200

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किन्तु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा.

**स्पष्टीकरण:-** विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" का तात्पर्य चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के किसी भाग से होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" का तात्पर्य आठ घंटे से कम अवधि से नहीं होगा."

20. उक्त विनियमनों के विनियमन 42 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(3) 1 नवंबर, 2020 से स्थानांतरण पर अधिकारी के पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान बीमा आदि से जुड़े व्ययों के लिए एकमुश्त राशि आहरित करने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात् :-

**तालिका**

क्र. सं.	श्रेणी या वेतनमान	राशि
1.	(1)	(2)
2.	शीर्ष कार्यकारी और वरिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	रु. 30,000/-
3.	मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु. 25,000/-

21. उक्त विनियमों के विनियम 45 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, यथा :-

"बशर्ते कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत कवर किए गए अधिकारियों के (नई पेंशन योजना) संबंध में, बैंक 11 नवंबर, 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते का चौदह प्रतिशत योगदान देगा :

बशर्ते कि नई पेंशन योजना के सेवा प्रदाता या निधि प्रबंधक का सेवा शुल्क वित्तीय वर्ष 2020-21 से बैंक द्वारा वहन किया जाएगा”.

22. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

**"अनुसूची"**

**[विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें]**

1 नवंबर, 2017 से, अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि उन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से वापस नहीं लिया जाता या संशोधित नहीं किया जाता, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात:-

**तालिका**

**विशेष क्षेत्र भत्ता**

क्र. सं.	क्षेत्र	भत्ते (रु.)	
		रु.36,001/- से कम वेतन	रु.36,001/- से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>मिजोरम</b> (ए) चिंपतुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक दूर के क्षेत्र; (बी) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला; (सी) सम्पूर्ण आइजोल जिला	4000 3200	5200 4200
2.	<b>नागालैंड</b>	3200	4200
3.	<b>अंडमान व निकोबार द्वीप समूह</b> (ए) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार और नारकोण्डम द्वीप समूह (बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4000 3200	5200 4200
4.	<b>सिक्किम</b>	4000	5200
5.	<b>लक्षद्वीप द्वीप समूह</b>	4000	5200
6.	<b>असम</b>	640	800
7.	<b>मेघालय</b>	640	800
8.	<b>त्रिपुरा</b> (ए) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र (बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण त्रिपुरा	3200 2400	4200 3000
9.	<b>मणिपुर</b>	2400	3000
10.	<b>अरुणाचल प्रदेश</b> (ए) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र (बी) दुर्गम क्षेत्रों के अलावा सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश	4000 3200	5200 4200
11.	<b>जम्मू एवं कश्मीर</b> (1) कठुआ जिला: निआबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4000	5200

	(2) उधमपुर जिला: (ए) डूडू बसंतगढ़, लेंडर भागम इलाका, भाग 2 (बी) में शामिल क्षेत्रों के अलावा). (बी) तहसील मोहरे में कंबन से गोयल तक का क्षेत्र और केसई की से अरनास तक का क्षेत्र.	4000 3200	5200 4200
	(3) डोडा जिला: किश्तवाड़ तहसील में पडुर और नियाबत नौगाम के इलाके	4000	5200
	(4) लेह जिला: जिले के सभी स्थानों पर	4000	5200
	(5) बारामूला जिला: (i) संपूर्ण गुरेज़निराबत-, तंगडार उप-संभाग और केरन इलाका (ii) मैचिल	4000 3200	5200 4200
	(6) पुंछ और राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र, पुंछ और राजौरी और सुंदरबनी के शहरों और दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर	2400	3000
	(7) वे क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (6) में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थान जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ते हेतु योग्य घोषित किया जा सकता है.	2400	3000
12.	<b>हिमाचल प्रदेश</b> (1) चम्बा जिला (ए) एपांगी तहसील ( भरमौर तहसील, पंचायतें बड़गांव :, बजोल, देवल कुगती, नयागाम और टुण्डा, गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी  (बी) भरमौर तहसील, उपरोक्त (ए) में शामिल पंचायतों एवं गांवों को छोड़कर.  (सी) भटियात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बनीखेत सहित).	4000 3200 2400	5200 4200 3000
	(2) किन्नौर जिला: (ए) असरंग, चित्कुल और हांगो कूनोचरंग पंचायतें/, छोटा खंबा, नाथपा और रूपी की ग्राम पंचायतों वाला 15/20 क्षेत्र पूह उप-संभाग, उपर्युक्त पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर. (बी) उपरोक्त (i) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण जिला.	4000 3200	5200 4200
	(3) कुल्लू जिला: (ए) निरमांद तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं. (बी) [बाहरी सराज (निरमांद तहसील में जकात-खाना और बुररो के गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला, बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबिस के परगना को छोड़कर, लेकिन तहसील निरमांद के जगत-खाना और बुररो गांव सहित]	4000 2400	5200 3000

(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4000	5200
(5) शिमला जिला : (ए) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबानासदाना-, सरपारा और चांदी-ब्रंदा की पंचायतें शामिल हैं. (बी) डोडरा-क्कार तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और परगना सराहन का मुनीश, गोरीचैबीस. (सी) चौपाल तहसील और घोरीस, पंजगांव, पाटसनऊ, नौबीस और सराहन परगना की तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, बारबीस परगना, रामपुर तहसील के रामपुर परगना का कस्बा रामपुर और गौरी नोग, शिमला शहर और इसके उपनगर (ढल्ली, जटोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू).	4000 3200 2400	5200 4200 3000
(6) कांगड़ा जिला (ए) बड़ा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र  (बी) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर तथा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित परन्तु धर्मशाला शहर में सम्मिलित निम्नलिखित कार्यालय-महिला आईटीआई, दारी, यांत्रिक कार्यशाला, रामनगर, बाल कल्याण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, सकोह, सीआरएसएफ कार्यालय निचला सकोह, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, डुगियार, एचआरटीसी कार्यशाला, सधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आई.पी.एच. उप-मंडल, दान, बंदोबस्त कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर.  कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर, जिसमें पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर और इसकी नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन पालमपुर शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं -हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर, पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बंडला, विद्युत उप-मंडल, लोहना, डीपीओ निगम, बंडला, विद्युत एचईएसईई डिवीजन, घुग्गर.	3200  2400	4200  3000
(7) मंडी जिला:  जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील की पंचायतें - बगड़ा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गटू, गरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार, कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना, धर्मपुर ब्लॉक की पंचायतें -बिंगा, कमलाह, सकलाना, तन्यार और ताराखोला, करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुडी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें -बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा.	2400	3000
(8) सिरमौर जिला: बानी, बाखली (पछाड़ तहसील), भरोगभनेरी (पांवटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बर (पछाड़ तहसील) और थानाकसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरि क्षेत्र की पंचायतें	2400	3000

	(9)सोलन जिला: मंगल पंचायत	2400	3000
	(10)हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1)से (9)में शामिल नहीं हैं.	640	800
.13	उत्तर प्रदेश: चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4000	5200
.14	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4000	5200
15.	पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भानातुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगखाली, सजनाखाली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पाथरप्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सिकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुशियोघाटा (कुल्टी)	1000	1000

वास्ती वेंकटेश, महा प्रबन्धक- मासंप्र

[विज्ञापन-III/4/असा./715/2024-25]

**नोट:** मूल विनियम 1 जुलाई, 1979 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में भारत के राजपत्र में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात्: -

क्र.सं.	राजपत्र अधिसूचना सं.	सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	43	24.10.1987
2.	16	21.04.1990
3.	43	25.10.1996
4.	37	13.09.1998
5.	42	20.10.2001
6.	26	28.06.2003
7.	79	15.05.2006
8.	115	29.07.2006
9.	361	11.12.2014
10.	275	11.07.2017
11.	63	28.01.2022

#### विवरणात्मक ज्ञापन

ये विनियम जो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए हैं, वे भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों की सहमत शर्तों के अनुसार हैं. इसलिए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.



**CENTRAL BANK OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th November, 2024

**No. CO:HCM:IRP:2024-25:295.**—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Central Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (i) These regulations may be called the Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.
- (ii) Save as provided in these Regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of November 2017.
2. In the Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,-
- (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“(f) “family” for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession means, the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children) wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty percent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters and parents wholly dependent on the officer.

***Explanation.-***

- (i). The expression “wholly dependent family member” shall mean such member of the family having an income not exceeding ₹12,000/- per month. If the income of one of the parents exceeds ₹12,000/- per month or the aggregate income of both the parents exceeds ₹12,000/- per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.
- (ii). A married female officer may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both, provided that the parents or parents-in-law are wholly dependent on her.

**Note (1):** For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all officers' i.e., male or female, any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered. The officer will have the choice to substitute either of the dependents or both.

**Note (2):** Physically challenged children of an officer to be defined as dependents irrespective of age or marital status, subject to income criteria;”

- (iii) In regulation 3 of the said regulations, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“Managing Director” means the Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank;.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

(iii) In sub-regulation (6), the *Explanation* shall be omitted;

(iv) for sub-regulations (7) and (8) , the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(7) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2017, the scales of pay specified against each grade shall be as under:-

(a) Top Executive Grade

Scale VII = ₹ 116120 – 3220/4 – 129000

Scale VI = ₹ 104240- 2970/4 – 116120

(b) Senior Management Grade

Scale V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

Scale IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

## (c) Middle Management Grade

Scale III = ₹ 63840-1990/5- 73790 - 2220/2 - 78230

Scale II = ₹ 48170-1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

## (d) Junior Management Grade

Scale I = ₹ 36000-1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

*Explanation.*- Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31<sup>st</sup> October, 2017 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1<sup>st</sup> November, 2017 on stage-to-stage basis, i.e., on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(8) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5), (6), and (7) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(9) (a) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:-

Scale I – III - 7.75 percent of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 10 percent of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII - 11 percent of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

(9) (b) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:-

Scale I – III - 16.40 percent of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 percent of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 20 percent of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to in clause (a) and (b) of sub-regulation 9 with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation, shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulations (7) and (8) of regulation 4, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (7) and (8) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increments in the next higher Scale only as specified in clause (c) and (d) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 1990/- each and the next three of Rs. 2220/- each;

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1<sup>st</sup> November, 2017, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments of Rupees 2220/- for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1<sup>st</sup> November, 2017, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III i.e., those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for six stagnation increments out of which first four stagnation increments of Rs 2220/- each will be granted for every two years of completed service after reaching the maximum and the next two stagnation increments of Rs 2500/- each shall be granted for every two years of completed service after receiving the fourth stagnation increment:

Provided that the sixth stagnation increment shall be released two years after release of fifth stagnation increment or on the 1<sup>st</sup> November, 2017, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for two stagnation increments after reaching the maximum of scale for every two completed years of service, of which first stagnation increment shall be of Rs 2500/- and the second stagnation increment shall be of Rs 2730/-:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment two years after release of first stagnation increment or on the 1<sup>st</sup> November, 2017, whichever is later;

- (g) the stagnation increments received by the officers from Scale I to Scale IV during their service in Bank as on the 1<sup>st</sup> November, 2017 as per periodicity hereinbefore would be readjusted from three years periodicity to two years periodicity from the date of reaching their maximum and officer shall be notionally eligible for stagnation increments w.e.f the 1<sup>st</sup> November, 2017 as per the revised periodicity which will qualify for superannuation benefits. However, monetary benefit on account of such revised and readjusted periodicity of stagnation increments shall be payable from 1<sup>st</sup> November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later;
- (h) officer in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for one stagnation increment of Rs 2970/- two years after reaching the maximum scale of pay or on the 1<sup>st</sup> November 2020, whichever is later:

Provided that such increments shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

**Explanation.-** Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (ii) In sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (g) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(h) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, other things being equal, the quantum of professional qualification pay shall stand revised as specified in the Table below:-

**TABLE**

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	(i) Rs.1020 per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the Scale. (ii) Rs.2550 per month two years after reaching maximum of the Scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of professional qualification pay and the release of subsequent installments of professional qualification pay shall be with reference to the date of release of first installment of professional qualification pay.”;

(iii) (a) In sub-regulation (3), after the table under clause (f), Note to be omitted;

(b) In sub-regulation (3), after the table under clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

“(g) on and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, other things being equal, fixed personal pay together with house rent allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

**TABLE**

Sl. No.	Increment component (Rs.)	Dearness Allowance as on 1 <sup>st</sup> November, 2017 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
	(1)	(2)	(3)
1	1990	53	2043
2	2220	59	2279
3	2500	66	2566
4	2730	73	2803
5	2970	79	3049
6	3220	86	3306

**Note:**

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5), (6) and (7) of regulation 4 is earned;
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before 1<sup>st</sup> November, 1993, will be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1<sup>st</sup> November 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of professional qualification pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1<sup>st</sup> November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of professional qualification pay, if any, shall be released on the 1<sup>st</sup> November, 2000.

- (v) The increment component of fixed personal allowance or fixed personal pay shall rank for superannuation benefits.
  - (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) above, one year after reaching the maximum of the scale.”.
5. In regulation 20 of the said regulations, in sub-regulation (1) in clause (c), the words “Managing Director” shall be substituted by “Managing Director and Chief Executive Officer.”.
  6. In regulation 21 of the said regulations,-
    - (i) after sub-regulation (6), the Explanation (a) and (b) shall be omitted;
    - (ii) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-
 

“(7) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.07% of Pay.”.

*Explanation.* - For the purposes of this sub-regulation,-

(a) “pay” for the purpose of dearness allowance shall mean basic pay including stagnation increments plus special allowance;

(b) Professional qualification allowance or professional qualification pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g) and (h) to the *explanation* in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.”

7. “In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017,-

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.50 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
2.	Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
3.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
4.	Other places	7.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.50 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (3) of the above Table.

Note:- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.”.

8. In regulation 23 of the said regulations,-

(a) For sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, if an officer is serving in a place mentioned in Column (2) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in Column (3) thereof against that place shall be payable.

**TABLE**

Sl. No.	Places	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Places in Area 1 and above and in the State of the Goa	Rs. 1400/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1150/- per month

(2) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, the rates of special area allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.

- (3) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group 'A' or Group 'B' respectively.
- (4) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2020, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs 1650/- per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2020, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum of Rs.6000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs 3000/- per month:

Provided further that an officer on deputation to the training establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum of Rs.3000 per month.”:

- (b) For sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(8) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.300 per month.”;

- (c) For sub-regulation (10), before the Notes (a) and (b), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

“(10) On and from 1<sup>st</sup> November 2017, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sl. No	Place	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Place with an altitude of 1000 meters and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.1125/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1500/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs. 3000/- per month”;

- (d). After sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(11) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, an officer shall be eligible for learning allowance of Rs 600/- per month along with Dearness Allowance thereon.

(12) On and from 1<sup>st</sup> November, 2017, an officer shall be eligible for a fixed allowance of Rs.700/- p.m. who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance. This fixed allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, viz. pension including National Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.

(13) From the financial year 2020-21, Performance Linked Incentive shall be payable to all officers annually based on Operating Profit or Net Profit over and above the normal salary payable. The Performance Linked

Incentive matrix mentioned below shall decide the amount payable (in number of days of pay = Basic + Dearness Allowance) depending on the annual performance of the Bank:

Sl. No.	Year-over-Year growth in operating profit.	Number of days for which Salary (Basic + DA) shall be paid.
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	Nil
2.	5% to 10%	5 days
3.	> 10% to 15%	10 days*
4.	> 15%	15 days*
*3 <sup>rd</sup> and 4 <sup>th</sup> slabs are payable only if the Bank has Net Profit. If a Bank has growth in operating profit of 5 per cent and more, but there is no Net Profit, then minimum 2 <sup>nd</sup> slab of 5 days shall be payable.”.		

9. In regulation 24 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.10300/- per annum or the amount incurred whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.12300/- per annum or the amount incurred whichever is less

**Note.-** (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2017, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2017 and December, 2017.”.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1<sup>st</sup> November, 2017, a sum equal to 0.50 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.10 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”

11. In regulation 32 of the said regulations, in sub-regulation (2), after the proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely:-

“**Explanation.-** For the purpose of this regulation, it is clarified that-

- casual leave not availed in the year 2017 or any subsequent years shall lapse in the following five years;
- on and from 1<sup>st</sup> November, 2020, the unavailed Casual leave by the officer shall be permitted on medical grounds and no medical certificate is required for the period of such unavailed casual leave at a stretch not exceeding four days.”.

## 12. In regulation 33 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) On and from the 1<sup>st</sup> June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and forty days:

Provided further that from the calendar year 2020, an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an Officer who have already completed fifty-five years of age as on 1<sup>st</sup> January, 2020, and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement as a one-time measure.”.

(b) after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) An officer desiring to avail of privilege leave shall ordinarily give not less than ten days’ notice of his intention of avail of such leave except for the purpose of leave fare concession;

(6) Privilege Leave taken on sick grounds, when there is no credit in the sick leave account of the officer, shall not be counted as an occasion of availing Privilege Leave.”.

## 13. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(5) Women officers may avail sick leave for the sickness of their children of eight years and below subject to production of medical certificate.”.

## 14. For regulation 35 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“35. Additional sick leave.-(1) On and from 1<sup>st</sup> January, 1989, where an officer has put in a service of twenty-four years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of twenty-four years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

(2) On and from 1<sup>st</sup> November, 2017, where an Officer has put in thirty years of service, he shall be eligible for further additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of thirty years subject to a maximum of three months of additional sick leave:

Provided that the total number of sick leave shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer:

Provided further that in case of additional sick leaves availed on or after 29<sup>th</sup> June, 1999, commutation of additional leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of regulation 34.”.

## 16. For regulation 36 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“36 Maternity leave. -

(1) A female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave;

(2) in case of miscarriage, medical termination of pregnancy or abortion, a female employee may avail maternity leave upto six weeks on the basis of medical certificate or advice of a competent medical practitioner, i.e., a qualified gynecologist. In special or exceptional cases involving medical complications, associated with miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, maternity leave may be availed beyond six weeks, if advised by a competent medical practitioner (qualified gynecologist) but upto six months only on any one occasion, within the overall limit of twelve months during the entire period of service;

(3) Within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.



Note: In the case of employees who have availed and exhausted maternity leave of twelve months, leave of fifteen days shall be sanctioned over and above the same, subject to production of medical certificate;

- (4) a childless female employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;
- (iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
- (v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service;

- (5) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hospitalization on account of the following gynecological ailments or treatments upto a maximum of thirty days, namely:-

- (i.) AUB (Abnormal uterine bleeding);
- (ii.) Ovarian Tumor;
- (iii.) Tubectomy or Tubectomy reversal;
- (iv.) Post-Partum Depression (PPD);
- (v.) Post-Partum Hemorrhage (PPH);
- (vi.) Acute Pelvic Inflammatory Disease (Acute PID);
- (vii.) Dysfunction Uterine Bleeding; Dysfunction (DUB).

- (6) In case of Paternity Leave, with effect from the 1<sup>st</sup> June, 2015, male employees with upto two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave may be availed upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child:

Provided further that paternity leave as above shall be allowed to a male employee with upto two surviving children for legally adopting a child who is below one year of age.”.

17. For regulation 37 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“37. Extraordinary leave,-

- (1) An officer shall be eligible for extraordinary leave on loss of pay for not more than twenty-four months during the entire period of service.
- (2) An officer may avail extraordinary leave on any one occasion for a period not exceeding three months and, in extreme medical circumstances, he may avail extraordinary leave upto four months on any one occasion.

**Note:** The employee will not be losing any seniority on account of availing extraordinary leave on medical grounds.”.

18. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“37A Special Casual Leave and Special Leave,-

- (1) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc.

(2) With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) An officer may also be granted special casual Leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

19. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) Halting Allowance- On and from the 1<sup>st</sup> November, 2020, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to ‘per diem’ halting allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Grades/Scales of officers	Metro Rs.	Major ‘A’ Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
	(1)	(2)			
2.	Officers in Scale VI and above	2700	1950	1650	1425
3.	Officers in Scale IV and V	2250	1950	1650	1425
4.	Officers in Scale I, II and III	1950	1650	1425	1200

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, halting allowance at half the above rates shall be payable.

**Explanation.-** For the purpose of computing halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.”.

20. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1<sup>st</sup> November, 2020, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Grade or Scale	Amount
1.	(1)	(2)
2.	Top executive and senior management (officers in Scale IV and above)	Rs.30,000/-
3.	Middle management and junior management (officers upto Scale III)	Rs.25,000/-.

21. In regulation 45 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following provisos’ shall be inserted, namely:-

“Provided that with regard to officers covered under Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), the Bank shall make a contribution of fourteen per cent of pay plus dearness allowance with effect from the 11<sup>th</sup> November, 2020:

Provided further that the service charges of the Service Provider or Fund Manager of New Pension Scheme shall be borne by the Bank from the financial year 2020-21.”

22. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

## “Schedule”

[See sub-regulation (2) of regulation 23]

With effect from the 1<sup>st</sup> November, 2017, an officer shall be eligible for the special area allowances till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

**TABLE**  
**Special Area Allowance**

Sl. No.	AREA	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.36,001/-	Pay above Rs.36,001/-
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>	<b>Mizoram</b>		
	(a) Chimgtuipui district and areas beyond 25 kilometers from Lunglei town in Lunglei district;	4000	5200
	b) entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town;	3200	4200
	c) entire Aizawl district	2400	3000
<b>2.</b>	<b>Nagaland</b>	3200	4200
<b>3.</b>	<b>Andaman and Nicobar Islands</b>		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4000	5200
	(b) South Andaman (including Port Blair)	3200	4200
<b>4.</b>	<b>Sikkim</b>	4000	5200
<b>5.</b>	<b>Lakshadweep Islands</b>	4000	5200
<b>6.</b>	<b>Assam</b>	640	800
<b>7.</b>	<b>Meghalaya</b>	640	800
<b>8.</b>	<b>Tripura</b>		
	(a) Difficult areas of Tripura	3200	4200
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	2400	3000
<b>9.</b>	<b>Manipur</b>	2400	3000
<b>10.</b>	<b>Arunachal Pradesh</b>		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4000	5200
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	3200	4200
<b>11.</b>	<b>Jammu &amp; Kashmir</b>		
	(a) Kathua district: NiabatBani, Lohi, Malhar and Machhodi	4000	5200
	(b) Udhampur district:		
	(i) DuduBasantgarh, Lander BhamagIllaqa, other than those included in Part 2(b).	4000	5200
	(ii) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	3200	4200
	(c) Doda district: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	4000	5200
	(d) Leh district : all places in the district	4000	5200
	(e) Barmulla district:		
	(i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and KeranIllaqua	4000	5200
	(ii) Matchill	3200	4200
	(f) Poonch and Rajouri district : areas in Poonch and Rajouri district excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2400	3000
	(g) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kilometers from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	2400	3000

<b>12.</b>	<b>Himachal Pradesh</b>		
	(1) Chamba district		
	(a) Pangi tehsil, Bharmour tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4000	5200
	(b) Bharmour tehsil, excluding panchayats and villages included in (a) above.	3200	4200
	(c) Jhandru panchayat in Bhatiyat tehsil, Churah tehsil, Dalhousie town (including Banikhet proper).	2400	3000
	(2) Kinnaur district:		
	(i) Asrang, Chitkul and HangoKuno/ Charang Panchayats, 15/ 20 Area comprising the gram panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rupi, Pooh sub-division, excluding the panchayat areas specified above.	4000	5200
	(ii) entire district other than areas included in (a) above.	3200	4200
	(3) Kullu district:		
	(i) 15/20 area of Nirmand tehsil, comprising the gram panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4000	5200
	(ii) [Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of tehsil Nirmand]	2400	3000
	(4) Lahaul and Spiti district : entire area of Lahaul and Spiti	4000	5200
	(5) Shimla district :		
	(i) 15/20 area of Rampur tehsil comprising of panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	4000	5200
	(ii) Dora-Kawar tehsil, gram panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath tehsil and Munish, Ghorichaibis of ParganaSarahan.	3200	4200
	(iii) Chopal tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of ParganaSarahan, Deothi gram panchayat of Taklesh area, ParganaBarabis, Kasba Rampur and Ghoris Nog of Pargana Rampur of Rampur tehsil, Simla town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	2400	3000
	(6) Kangra district:		
	(i) Areas of Bara Bhargal and ChhotaBhargal	3200	4200
	b) Dharamshala town of Kangra district and the following offices located outside the municipal limits but included in Dharamshala town- Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and town and Country Planning offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar.	2400	3000
	Palampur town of Kangra district including HPKV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.		

	(7) Mandi district:  Chhuhar Valley of Jogindernagar tehsil, Panchayats in thunag tehsil-of Bagraa, Chatra, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, panchayats of Karsog tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	2400	3000
	(h) Sirmaur district:  Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad tehsil), BharogBheneri (Paonta tehsil), Birla (Nahan tehsil), Dibber (Pachhad tehsil) and ThanaKasoga (Nahan tehsil) and Thansgiri Tract	2400	3000
	(9) Solan district : Mangal Panchayat.	2400	3000
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	640	800
13.	<b>Uttar Pradesh:</b>  Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttarkashi districts	4000	5200
14.	<b>Uttarakhand:</b>  Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts	4000	5200
15.	<b>West Bengal</b> <b>South 24 Pargana district</b>  Sunderban areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhanatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhingakhali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, PatharPratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalgaanj, Basanti, kuemari, Kultola, Ghushioghata (Kulti)	1000	1000.”.

VASTI VENKATESH, General Manager-HCM

[ADVT.-III/4/Exty./715/2024-25]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India on 1<sup>st</sup> day of July, 1979 and subsequently amended *vide* the following notifications published in the Gazette of India, namely:-

Sr. No.	Gazette Notification No.	Date of publication in the official gazette
1.	43	24.10.1987
2.	16	21.04.1990
3.	43	25.10.1996
4.	37	13.09.1998
5.	42	20.10.2001
6.	26	28.06.2003
7.	79	15.05.2006
8.	115	29.07.2006
9.	361	11.12.2014
10.	275	11.07.2017
11.	63	28.01.2022

**EXPLANATORY MEMORANDUM**

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.